



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

दिनांक : 9/10/2020

पत्रांक : २२३

/एम०पी०/जॉन-१/२०२०-२१

मानचित्र संख्या : MAP20190206144122753

सेवा में,

मानचित्र स्वीकृति पत्र

मै० ज्योति सुपर कन्स्ट्रक्शन एण्ड हाउसिंग प्रा० लि०,
द्वारा डायरेक्टर श्री उदयवीर सिंह,
आफिस-१२१०, टावर-ए, कोरेन्थम, ए-४१,
सैक्टर-६२, नोएडा।

महोदय,

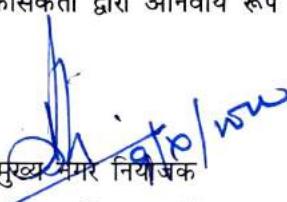
आपके प्रार्थना पत्र दिनांक ०७.०२.१९ के सन्दर्भ में खसरा सं०-११८१पि०, व ११८३पि० ग्राम नूरनगर जिला गाजियाबाद पर प्रस्तुत ले-आउट मानचित्र पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

१. यह मानचित्र स्वीकृति दिनांक २६.१०.२०१९ से केवल पांच वर्ष अर्थात दिनांक २५.१०.२०२४ तक वैध है।
२. मानचित्रों की इस स्वीकृति से सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी०डी०ए०) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
४. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
५. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
६. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि मुख्य सड़क की ओर न खुले।
७. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के विरुद्ध कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
८. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
९. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
१०. वह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-१९७३ की धारा-१५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
११. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
१२. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
१३. आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं इण्डीमेन्टी बॉण्ड दिनांक ०४.०५.१९ व ०३.०५.२०१९ का पालन करना होगा।
१४. पर्यावरण की दृष्टि से ३०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम ५० पेड़ लगाना एवं लैण्ड स्केप प्लान के अनुसार ग्रीन एरिया का विकास किया जाना अनिवार्य है।
१५. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लाये।
१६. भवन उपयोग से पूर्व भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
१७. १२ मी० से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

-क्रमश-

(2)

18. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि ग्रह विश्राम ग्रह, छात्रवास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थायें, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंकवेट हॉल, भारत घर व 500 वर्ग मी० से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करनी होगी।
19. संरचना सुरक्षा व स्पेसिफिकेशन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। संरचना सुरक्षा व भूकम्परोधी सम्बन्धी समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
20. आवेदक/भू-स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सेस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण ज़िम्मेदारी होगा। लेबर सेस की अवशेष धनराशि स्वयं श्रम विभाग में जमा कराकर रसीद प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
21. अतिरिक्त शर्तें मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चला कर दी गयी हैं। जिनका अनुपालन विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
संलग्नक: एक सैट स्वीकृत मानचित्र।


मुख्य नगर नियोजक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

दिनांक:

पत्रांक: /एम०पी०/जौन-१/२०२०-२१

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जौन-१ को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अतिरिक्त शर्तें

- प्रस्तावित भवन में रुफ टाप रेन वाटर हार्डिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रु. 2,00,000/- की जमानत राशि के रूप एफ0डी0आर0 दिनांक 25.09.20, एच.डी.एफ.सी. बैंक की जमा करायी गयी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्डिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- भवन का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- नगर निगम विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या- 2690 /सम्पत्ति/ 2019-20 दिनांक 22.02.2020 के अनुसार उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
- तहसीलदार का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.2020 प्रस्तुत किया गया है।
- प्रदूषण विभाग, उ0प्र0 का अनापत्ति प्रमाण प्रमाण हेतु शपथ पत्र दिनांक 22.09.2020 में उल्लेख किया गया है कि प्रदूषण विभाग की एन.ओ.सी. के लिए उनके द्वारा आवदेन किया गया है, जो प्राप्त होती ही प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
- हिण्डन एफर फोर्स, गाजियाबाद का अनापत्ति प्रमाण प्रमाण हेतु शपथ पत्र दिनांक 22.09.2020 में उल्लेख किया गया है कि सम्बन्धित विभाग में एन.ओ.सी. के लिए उनके द्वारा आवदेन किया गया है, जो प्राप्त होती ही जमा कर दिया जायेगी।
- वेस्ट वाटर रि-साइकिलिंग सिस्टम का सदुपयोग सुनिश्चित करना होगा।
- भवन का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
- आतंरिक विकास शुल्क के मद में बंधक भूखण्ड संख्या- जी+13 तक कुल क्षेत्रफल 20.00 वर्ग मी एवं बाह्य विकास शुल्क के मद में भूखण्ड संख्या- 72ए, 74 से 92, 92ए से 98 तक कुल क्षेत्रफल 2394.12 वर्ग मी है जिसका विक्रिय बंधक भूमि को अवमुक्त करने के पश्चात ही कराना होगा।
- भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्रॉइंग आई.आई.टी रुड़की के प्रोफेसर डा० ए० चक्रवर्ती से वैट कराकर प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार ही स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1- 2001-भूकम्परोधी/2001(आ.ब) दिनांक 03.02.01, 772/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी/2001(आ.ब) दिनांक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-(
(क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबन्धित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
(ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रिट, ईंटें, कोर्स सैन्ड एवं मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।
(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक किमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं

1 2 3 4 5

सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे : -

- i. नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति
- ii. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ
- iii. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल
- iv. अधिकृत आर्किटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सैक्षण एवं एलीवेशन तथा सर्विसिज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे
- v. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड पी. का विवरण
- vi. साईट इंजीनियर इन्सैपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
- vii. सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

11. फायर विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या- यू.पी.एफ.एस./2020/17345/जीजैडबी/गाजियाबाद/1317/डी०डी० दिनांक 24.02.2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
12. रेन वाटर हार्डेस्टिंग व्यवस्था का प्राविधान भवन की फिनिशिंग का कार्य से पहले पूर्ण कराना होगा।
13. सोलर वाटर हीटिंग इक्यूपमेन्ट सिस्टम का प्राविधान बी.आई.एस. कोड के अनुसार एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप करना होगा।
14. रोड वाइडेनिंग से प्रभावित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य न होगा तथा बाउन्ड्रीवाल रोड वाइडेनिंग के उपरान्त बनानी होगी।
15. प्रश्नगत सम्पूर्ण क्षेत्र द्वारा बाह्य विकास शुल्क के मद में 75 प्रतिशत धनराशि प्राप्त की दशा में ही इस क्षेत्र में बाह्य विकास कराने सम्भव होंगे तथा आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं कराने होंगे।
16. आन्तरिक विकास कार्यों हेतु बंधक होने वाली भूमि पर निर्माण की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि जब तक आन्तरिक विकास पूर्ण कर बंधक भूमि को अवमुक्त कराने के उपरान्त ही विक्रय किये जाने की अनुमति मान्य होगी।
17. 10 प्रतिशत ग्रीन पार्क के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य एवं शमनीय नहीं होगा।
18. विकलांग एवं आशक्त व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा। विकासकर्ता को सर्विस प्लान प्रस्तुत करना होगा जिसमें इन्फास्ट्रक्चर सुविधाएं जैसे-सड़क, सीवर, सीवर डिस्पोजल, ड्रेन, ड्रेन डिस्पोजल, पीने के पानी की व्यवस्था, भू-गर्भ जल उपयोग किये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति एवं सोलिड वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था दर्शानी होगी।
19. स्थल पर कम से कम 125 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित करना होगा।
20. होटल में दूर संचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार टेलीकॉम वायरिंग आदि की व्यवस्था करनी होगी।
21. आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं करने होंगे, तथा सीवर डिस्पोजल की व्यवस्था हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्वयं निर्मित करना होगा।
22. कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं प्रवेश द्वारा के समीप भूतल पर बॉयो डि ग्रेडेविल तथा नॉन बॉयो डि ग्रेडेविल डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी।
23. विद्युत व्यवस्था हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन से स्वयं कनैक्शन प्राप्त करना होगा।
24. अन्दर के खुले स्थल/पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
25. मानचित्र स्वीकृति, भू-स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
26. 10 प्रतिशत ग्रीन पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा तथा जन-सामान्य हेतु खुला रखना होगा। अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
27. भविष्य में कोई बढ़ा हुआ विकास शुल्क या अन्य किसी शुल्क की माँग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा कराना होगा।
28. विभिन्न मदों में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।
29. योजना का लेवल रोड के सापेक्ष नियमानुसार रखना होगा, जिससे कि ड्रेन का डिस्पोजल सुचारू रूप से हो सके।



30. निर्माण के समय यदि कोई दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
31. नेशनल बिल्डिंग कोड-2005/भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के अनुसार होटल हेतु आवश्यक समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना होगा।
32. स्थल पर निर्माण के समय लेबर हेतु जन-सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
33. विकासकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि माँग-पत्र में लगाये गये समस्त शुल्क मान्य हैं तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जाएगा।
34. प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 22.09.2020 व अन्य शपथ पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से आवेदक को करना होगा, अन्यथा कि स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
35. विकासकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिनांक 06.10.2020 प्रस्तुत किया गया है कि माँग-पत्र में लगाये गये समस्त शुल्क मान्य हैं तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जाएगा।
36. कार्य योजना के अनुसार कलेक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन व एम.एस.डब्लू. के डिस्पोजल हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
37. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा।
38. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जायें, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जायें एवं डस्ट सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायें। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जायें।
39. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 21/2014/ में अलग अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1760/पी०एस०एम०एस०/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-५-२०६-२९रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा –

 - i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
 - ii. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
 - iii. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
 - iv. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
 - v. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
 - vi. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
 - vii. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
 - viii. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
 - ix. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
 - x. Wind breaking walls around construction site.
 - xi. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
 - xii. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
 - xiii. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
 - xiv. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
 - xv. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.



xvi. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.

xvii. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.

xviii. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.

xix. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.

xx. Overloading is another big challenge and shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.

xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean Nox traps (LNTs).

xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.16 में उल्लेखित धनराशि पेनल्टी के रूप में वसूल की जायेगी।

40. स्वीकृत मानचित्र पर अवशेष धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा किये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदया के अनुमोदन दिनांक 01.09.2020 के क्रम में निमानुसार भुगतान करना होगा:-

क्र0 सं0	मूल धनराशि (रु0 में)	ब्याज की धनराशि (रु0 में)	कुल धनराशि (रु0 में)	देय तिथि
1.	52,08,937.00	12,50,145.00	64,59,082.00	04.02.2021
2.	52,08,937.00	9,37,609.00	61,46,546.00	04.08.2021
3.	52,08,937.00	6,25,072.00	58,34,009.00	04.02.2022
4.	52,08,939.00	3,12,536.00	55,21,475.00	04.08.2022

उपरोक्त किश्तों का भुगतान नियत तिथि पर करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।

41. बंधक भूमि को मानचित्र पर लाल रंग से दर्शित किया गया है, जिसे सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

अवर अभियन्ता

नगर नियोजक

मुख्य नगर नियोजक